नईदुनिया

संपादकीय

विकास के दावों और जमीनी सच्चाई के बीच

जबलपुर जिले में एक प्रसूता महिला की समय पर चिकित्सा सहायता न मिलने और अस्पताल पहुंचने से पहले मृत्यु हो जाने की घटना केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि उन दावों पर गंभीर प्रश्नचिह्न है जो प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं के व्यापक विस्तार के संबंध में किए जाते हैं। यदि किसी महिला को खराब सड़क, समय पर एंबुलेंस न मिलने और चिकित्सा व्यवस्था की कमियों के कारण अपनी जान गंवानी पड़े, तो यह केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि व्यवस्था की विफलता का संकेत है।

पिछले वर्षों में प्रदेश में सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपातकालीन सेवाओं के विस्तार के अनेक दावे किए गए हैं। आंकड़ों और घोषणाओं में विकास दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक परीक्षा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली सुविधाओं से होती है। जब किसी गांव की सड़क बारिश में दलदल में बदल जाए, जब एंबुलेंस समय पर न पहुंचे और जब अस्पताल इलाज के बजाय केवल रेफरल का केंद्र बनकर रह जाए, तब विकास के दावों की विश्वसनीयता कमजोर पड़ जाती है।

स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति विशेष चिंता का विषय है। 108 एंबुलेंस सेवा और प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने के लिए सरकारों ने अनेक योजनाएं लागू की हैं, लेकिन इनकी सफलता का आकलन कागजी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि संकट की घड़ी में मिलने वाली सहायता से होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी डॉक्टरों की कमी, संसाधनों का अभाव और समय पर उपचार न मिल पाने जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। परिणामस्वरूप गरीब और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।

सड़क और स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारियों में शामिल होती हैं। यदि किसी गांव तक पहुंचने का रास्ता सुरक्षित और सुगम नहीं है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के सभी दावे अधूरे रह जाते हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं में छोटी-सी चूक भी किसी परिवार के लिए अपूरणीय क्षति का कारण बन सकती है। इसलिए ऐसी घटनाओं को केवल दुर्भाग्यपूर्ण कहकर टालना पर्याप्त नहीं है।

इस मामले में जिम्मेदारी तय होना आवश्यक है। संबंधित विभागों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि सड़क की स्थिति क्यों खराब थी, एंबुलेंस सेवा समय पर क्यों नहीं पहुंची और स्वास्थ्य संस्थानों में क्या कमियां रहीं। केवल जांच समिति गठित कर देना समाधान नहीं है। दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

यह घटना हमें याद दिलाती है कि विकास का वास्तविक अर्थ राजधानी की चमक या आंकड़ों की उपलब्धियां नहीं, बल्कि अंतिम गांव तक पहुंचने वाली बुनियादी सुविधाएं हैं। जब हर गांव तक पक्की सड़क पहुंचेगी, जब एंबुलेंस समय पर उपलब्ध होगी और जब अस्पतालों में आवश्यक संसाधन मौजूद होंगे, तभी विकास के दावों को सार्थक माना जा सकेगा। ममता की मृत्यु केवल एक परिवार का दुख नहीं है, बल्कि यह व्यवस्था के लिए चेतावनी है कि विकास के दावों और जमीनी सच्चाई के बीच की दूरी को अब और अनदेखा नहीं किया जा सकता।

कागज पर फसल, धरती पर संकट ...

खरीफ सीजन की दस्तक के साथ ही प्रदेश का किसान एक बार फिर उम्मीद और चिंता के दोराहे पर खड़ा है। अच्छी वर्षा के बाद खेतों में नमी है, बुवाई के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं और किसान नई फसल के सपने संजो रहा है। लेकिन इस आशा के बीच एक कड़वी सच्चाई भी है। प्रदेश के अनेक हिस्सों में किसान खाद, बीज और समय पर ऋण जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है। कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद यदि किसान को खेती शुरू करने के लिए आवश्यक संसाधन समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो यह व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

प्रदेश में खरीफ फसलों के लिए हर वर्ष बड़ी मात्रा में यूरिया, डीएपी और अन्य उर्वरकों की आवश्यकता होती है। इसके बावजूद लगभग हर सीजन में खाद की उपलब्धता को लेकर संकट की स्थिति बन जाती है। अनेक स्थानों पर किसानों को घंटों कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। कई बार उन्हें आवश्यक मात्रा में खाद नहीं मिल पाती और उन्हें बार-बार वितरण केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेती में समय का विशेष महत्व होता है। बुवाई के उपयुक्त अवसर के निकल जाने का अर्थ सीधे उत्पादन में कमी और आर्थिक नुकसान से है। इसलिए खाद की उपलब्धता केवल आपूर्ति का प्रश्न नहीं, बल्कि कृषि उत्पादन और किसान की आय से जुड़ा मुद्दा है।

बीजों की उपलब्धता और उनकी गुणवत्ता को लेकर भी किसानों की चिंताएं कम नहीं हैं। प्रमाणित और गुणवत्तापूर्ण बीज समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते, जबकि निजी कंपनियों के बीज अपेक्षाकृत अधिक कीमत पर बिकते हैं। किसान बेहतर उत्पादन की उम्मीद में महंगे बीज खरीदता है, लेकिन मौसम की प्रतिकूलता, कीट प्रकोप या अन्य कारणों से फसल प्रभावित होने पर उसकी पूरी आर्थिक गणना बिगड़ जाती है। ऐसे में जोखिम का अधिकांश भार किसान के कंधों पर ही आ जाता है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि कृषि को केवल योजनाओं और आंकड़ों के आधार पर न देखा जाए। खेतों की वास्तविक स्थिति, किसानों की चुनौतियों और स्थानीय आवश्यकताओं को समझकर नीतियां बनाई जाएं। खाद और बीज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ऋण प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई हो और फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को शीघ्र राहत मिले। साथ ही कृषि विपणन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाकर किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना भी आवश्यक है।

कृषि ऋण व्यवस्था की जटिलताएं भी किसानों की परेशानी बढ़ा रही हैं। संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने की अनेक योजनाएं होने के बावजूद अनेक किसानों को समय पर ऋण नहीं मिल पाता। दस्तावेजी प्रक्रियाएं, प्रशासनिक विलंब और विभिन्न औपचारिकताएं अक्सर बुवाई के महत्वपूर्ण समय को प्रभावित कर देती हैं। परिणामस्वरूप कई किसान निजी साहूकारों या गैर-संस्थागत स्रोतों से ऊंची ब्याज दरों पर ऋण लेने के लिए विवश हो जाते हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक कमजोर होती है।

खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। उर्वरक, बीज, कीटनाशक, डीजल, बिजली और मजदूरी पर होने वाला खर्च पहले की तुलना में काफी अधिक हो चुका है। इसके विपरीत किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित नहीं हो पाता। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा अवश्य होती है, लेकिन खरीद व्यवस्था की व्यावहारिक चुनौतियां किसानों को उसका पूरा लाभ लेने से रोकती हैं। कई बार किसानों को मजबूरी में अपनी उपज कम कीमत पर बेचनी पड़ती है। कीटनाशकों और कृषि आदानों की गुणवत्ता भी चिंता का विषय है। नकली या निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ उत्पादन को भी प्रभावित करते हैं। शिकायतों के निराकरण में देरी और निगरानी तंत्र की कमजोरियां समस्या को और गंभीर बना देती हैं। इसी प्रकार सिंचाई और ऊर्जा से जुड़ी चुनौतियां भी किसानों की लागत बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

सरकारों ने किसानों के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य उनकी आय बढ़ाना और जोखिम कम करना है। हालांकि इन योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी संभव है जब उनका क्रियान्वयन समयबद्ध और प्रभावी ढंग से हो। फसल बीमा, कृषि ऋण, उर्वरक वितरण और समर्थन मूल्य जैसी व्यवस्थाओं को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है। तकनीक का उपयोग किसानों की सुविधा बढ़ाने के लिए होना चाहिए, न कि प्रक्रियाओं को और जटिल बनाने के लिए।

आज आवश्यकता इस बात की है कि कृषि को केवल योजनाओं और आंकड़ों के आधार पर न देखा जाए। खेतों की वास्तविक स्थिति, किसानों की चुनौतियों और स्थानीय आवश्यकताओं को समझकर नीतियां बनाई जाएं। खाद और बीज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ऋण प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई हो और फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को शीघ्र राहत मिले। साथ ही कृषि विपणन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाकर किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना भी आवश्यक है।

किसान किसी विशेष अनुग्रह की अपेक्षा नहीं करता। वह केवल इतना चाहता है कि उसके श्रम का उचित सम्मान हो और खेती के लिए आवश्यक संसाधन समय पर उपलब्ध हों। देश की खाद्य सुरक्षा का आधार किसान है। यदि उसकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर नहीं किया गया तो इसका प्रभाव केवल कृषि क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समग्र विकास पर भी पड़ेगा। इसलिए समय की मांग है कि कृषि क्षेत्र की चुनौतियों को गंभीरता से लिया जाए और किसान को व्यवस्था के केंद्र में रखकर समाधान खोजे जाएं। तभी खेतों की हरियाली और किसानों की खुशहाली का सपना साकार हो सकेगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

कांचना जैसी बेटियां चौथे पायदान पर क्यों फिसल जाती हैं

नीट पीजी काउंसलिंग 2026 के आंकड़े भारतीय चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था की एक गंभीर वास्तविकता को उजागर करते हैं। 958 अभ्यर्थियों में से केवल 104 का चयन हुआ। यह संख्या केवल प्रतिस्पर्धा की कठिनाई नहीं बताती, बल्कि उस खाई की ओर भी संकेत करती है जो मेरिट और आर्थिक सामर्थ्य के बीच मौजूद है। आज केवल मेरिट सूची में स्थान प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं रह गया है। प्रवेश की अंतिम मंजिल तक पहुंचने के लिए आर्थिक संसाधनों का होना भी उतना ही आवश्यक होता जा रहा है।

कांचना जैसी अनेक प्रतिभाशाली छात्राएं और छात्र इस व्यवस्था की सबसे बड़ी पीड़ित हैं। एक बस कंडक्टर के बेटे या रेलवे कुली की बेटी के लिए चिकित्सा शिक्षा तक पहुंचने का रास्ता केवल कठिन नहीं, बल्कि कई बार लगभग असंभव हो जाता है। कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट रैंक हासिल करने के बावजूद प्रवेश प्रक्रिया के दौरान फीस, ऋण, बॉन्ड और अन्य आर्थिक बाधाएं उनके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। चयन और वास्तविक प्रवेश के बीच का यह अंतर आज शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।

उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि बड़ी संख्या में सफल अभ्यर्थियों ने महंगी कोचिंग और विशेष मार्गदर्शन का लाभ लिया है। दूसरी ओर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्र सीमित संसाधनों और ऑनलाइन सामग्री के सहारे तैयारी करते हैं। प्रतिस्पर्धा की शुरुआत भले समान परीक्षा से होती हो, लेकिन तैयारी के साधन और अवसर समान नहीं होते। यही असमानता आगे चलकर काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया में और स्पष्ट दिखाई देती है।

राज्यवार आंकड़े भी शिक्षा और आर्थिक विषमता का संकेत देते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली अभ्यर्थी चयनित होते हैं, लेकिन सरकारी मेडिकल कॉलेजों की सीमित संख्या और निजी संस्थानों की ऊंची फीस कई परिवारों के लिए गंभीर समस्या बन जाती है। परिणामस्वरूप अनेक छात्र चयनित होने के बावजूद प्रवेश नहीं ले पाते, जबकि आर्थिक रूप से सक्षम अभ्यर्थी उपलब्ध सीटों पर प्रवेश प्राप्त कर लेते हैं।

कोचिंग उद्योग का बढ़ता प्रभाव भी इस असंतुलन को गहरा कर रहा है। आज केवल परीक्षा की तैयारी ही नहीं, बल्कि काउंसलिंग रणनीति और कॉलेज चयन जैसी सेवाएं भी एक बड़े बाजार का रूप ले चुकी हैं।

आर्थिक रूप से सक्षम परिवार इन सुविधाओं का लाभ उठा लेते हैं, जबकि कमजोर वर्ग के छात्र सूचना और मार्गदर्शन के अभाव में अवसर खो देते हैं। इससे योग्यता और अवसर के बीच की दूरी बढ़ती जाती है।

बॉन्ड नीति और फीस संरचना भी कई बार आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए चुनौती बन जाती है। ग्रामीण सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई गई व्यवस्थाओं का प्रभाव सभी वर्गों पर समान नहीं पड़ता। दूसरी ओर अनेक संस्थानों में वास्तविक खर्च की पूरी जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं होती, जिससे अभ्यर्थियों और उनके परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ता है।

स्थिति में सुधार के लिए कुछ ठोस कदम आवश्यक हैं। सभी मेडिकल कॉलेजों को अपनी संपूर्ण फीस संरचना, हॉस्टल शुल्क, बॉन्ड राशि और अन्य व्ययों का विवरण काउंसलिंग शुरू होने से पहले सार्वजनिक करना चाहिए। चयनित आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए आसान और न्यूनतम ब्याज दर वाले शिक्षा ऋण की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। छात्रवृत्ति और फीस सहायता योजनाओं का दायरा भी बढ़ाया जाना आवश्यक है।

काउंसलिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और रियल टाइम सूचना आधारित बनाया जाना चाहिए। रिक्त सीटों और उनके आवंटन से संबंधित जानकारी समय पर उपलब्ध होने से अभ्यर्थियों को बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।

इसके अतिरिक्त सामाजिक संस्थाओं, पूर्व छात्रों और स्वयंसेवी संगठनों को भी प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए।

यह केवल किसी एक छात्र या परिवार का प्रश्न नहीं है। हर वर्ष हजारों प्रतिभाशाली अभ्यर्थी आर्थिक कारणों से चिकित्सा शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। यह न केवल व्यक्तिगत क्षति है, बल्कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी नुकसान है। विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों से आने वाले छात्र अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद समाज की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य केवल प्रतिभा की पहचान करना नहीं, बल्कि उसे अवसर उपलब्ध कराना भी होना चाहिए। यदि मेरिट आर्थिक बाधाओं के सामने हारने लगे तो यह किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए चिंता का विषय है। आवश्यकता इस बात की है कि चयन और प्रवेश के बीच की दूरी कम की जाए तथा ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए जिसमें किसी भी प्रतिभाशाली छात्र का भविष्य उसकी आर्थिक स्थिति से निर्धारित न हो। कांचना जैसी बेटियों का संघर्ष हमें यही संदेश देता है कि प्रतिभा देश के हर घर में जन्म लेती है, लेकिन उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी पूरे समाज और व्यवस्था की है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

आजकल

तालियों का बाजार और अकेला होता इंसान

सोशल मीडिया ने दुनिया को जोड़ने का काम किया है, लेकिन इसके साथ उसने एक ऐसी संस्कृति भी पैदा कर दी है, जिसमें व्यक्ति अपनी खुशियों और उपलब्धियों का मूल्य खुद नहीं, बल्कि दूसरों की प्रतिक्रियाओं से तय करने लगा है। आज किसी परीक्षा में सफलता मिले, नौकरी में प्रमोशन हो या कोई निजी उपलब्धि हासिल हो, उसे सोशल मीडिया पर साझा करना लगभग स्वाभाविक व्यवहार बन गया है। समस्या साझा करने में नहीं, बल्कि उस मानसिकता में है, जो खुशी को लाइक्स और कमेंट्स की संख्या से जोड़ देती है।

धीरे-धीरे यह प्रवृत्ति आत्मसंतोष को कमजोर करती है। व्यक्ति अपनी सफलता का आनंद लेने के बजाय यह देखने में अधिक व्यस्त हो जाता है कि कितने लोगों ने उसे नोटिस किया। परिणाम यह होता है कि उपलब्धियां स्थायी संतोष देने के बजाय क्षणिक उत्साह का साधन बन जाती हैं। डिजिटल दुनिया की तालियां थमते ही खुशी भी फीकी पड़ने लगती है।

यह केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का संकेत है। आज प्रदर्शन की संस्कृति ने जीवन के हर क्षेत्र में जगह बना ली है। लोग सफल होने से अधिक सफल दिखने की चिंता करने लगे हैं। तुलना, प्रतिस्पर्धा और मान्यता की यह दौड़ मानसिक तनाव, असंतोष और आत्मसम्मान के संकट को जन्म दे रही है।

वास्तविक उपलब्धि का मूल्य किसी एल्गोरिद्म या दर्शक संख्या से तय नहीं हो सकता। सफलता की असली कसौटी व्यक्ति का प्रयास, संघर्ष और सीख है। समाज को भी ऐसी संस्कृति विकसित करनी होगी, जहां व्यक्तित्व की पहचान डिजिटल लोकप्रियता से नहीं, बल्कि वास्तविक योगदान और मानवीय मूल्यों से हो।

लाइक्स खुशी दे सकते हैं, लेकिन आत्मविश्वास नहीं। आत्मसम्मान का सबसे मजबूत आधार दूसरों की स्वीकृति नहीं, बल्कि स्वयं की स्वीकृति होती है। जिस दिन यह बात समझ में आ जाएगी, उस दिन खुशी स्क्रीन पर नहीं, मन के भीतर दिखाई देगी।

अंतरिक्ष में 200 दिनः मानव शरीर का सबसे बड़ा परीक्षण

धरती से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर स्थित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अगले 200 दिनों तक एक अनोखे वैज्ञानिक प्रयोग का केंद्र बनने जा रहा है। नासा के अंतरिक्ष यात्री डॉ. अनिल मेनन इस अवधि में केवल अंतरिक्ष यात्री की भूमिका नहीं निभाएंगे, बल्कि स्वयं एक जीवित प्रयोगशाला बनकर मानव शरीर पर अंतरिक्ष के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। भारतीय मूल के डॉ. मेनन एक्सपीडिशन-74 और 75 मिशन के तहत सोयूज एमएस-29 यान से अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचेंगे और वहां लंबे समय तक रहने के दौरान अपने शरीर में होने वाले बदलावों का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार करेंगे।

अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव लगभग समाप्त हो जाता है। यह स्थिति मानव शरीर के लिए असामान्य है, क्योंकि पृथ्वी पर शरीर की लगभग सभी जैविक प्रणालियां गुरुत्वाकर्षण के अनुरूप विकसित हुई हैं। अंतरिक्ष में रक्त और अन्य तरल पदार्थ सिर की ओर बढ़ने लगते हैं, जिससे चेहरे पर सूजन, आंखों पर दबाव और दृष्टि संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके साथ ही हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है, मांसपेशियां कमजोर पड़ती हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली भी प्रभावित होती है। डॉ. मेनन इन सभी परिवर्तनों का नियमित अध्ययन करेंगे और प्राप्त आंकड़े पृथ्वी पर वैज्ञानिकों तक पहुंचाएंगे। यह मिशन केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों, विशेष रूप से मंगल मिशन से है। पृथ्वी से मंगल तक की यात्रा में लगभग नौ महीने लग सकते हैं और वापसी में भी उतना ही समय लगेगा। ऐसे में अंतरिक्ष यात्रियों को डेढ़ वर्ष तक लगभग शून्य गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में रहना पड़ सकता है। इतने लंबे समय तक मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को समझना अत्यंत आवश्यक है। डॉ. मेनन द्वारा एकत्रित किए जाने वाले आंकड़े भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए दवाओं, व्यायाम कार्यक्रमों और स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

डॉ. मेनन का अनुभव इस मिशन को और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। वे स्पेसएक्स के पहले फ्लाइट सर्जन रहे हैं और आपदा क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं देने का व्यापक अनुभव रखते हैं। हैती और नेपाल के भूकंपों से लेकर माउंट एवरेस्ट बचाव अभियानों तक उन्होंने कठिन परिस्थितियों में काम किया है। यही अनुभव उन्हें अंतरिक्ष में चिकित्सा अनुसंधान के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बनाता है। स्वयं उनके शब्दों में, वे पहले भी डॉक्टर थे और अंतरिक्ष में भी डॉक्टर ही रहेंगे, फर्क केवल इतना होगा कि इस बार मरीज वे स्वयं होंगे।

इस मिशन का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू अंतरिक्ष में चिकित्सा संसाधनों की उपलब्धता से जुड़ा है। डॉ. मेनन अंतरिक्ष स्टेशन के पुनर्चक्रित पानी से ग्लूकोज और सलाइन तैयार करने की तकनीक का परीक्षण करेंगे। अंतरिक्ष में पानी अत्यंत मूल्यवान संसाधन है और उसे पृथ्वी से पहुंचाना महंगा पड़ता है। यदि भविष्य में चंद्रमा या मंगल पर मानव बस्तियां स्थापित होती हैं, तो स्थानीय संसाधनों से चिकित्सा सामग्री तैयार करना अनिवार्य होगा। इस दिशा में यह प्रयोग महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

भारत के लिए भी यह मिशन विशेष महत्व रखता है। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्रियों की परंपरा में डॉ. मेनन एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं। उनकी उपलब्धि उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो विज्ञान, चिकित्सा और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपना भविष्य देख रहे हैं। साथ ही यह मिशन भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान कार्यक्रम के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है। लंबे अंतरिक्ष अभियानों में मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जो जानकारी इस मिशन से प्राप्त होगी, वह भारतीय वैज्ञानिकों और चिकित्सकों के लिए भी मूल्यवान होगी।

अंतरिक्ष अनुसंधान का लाभ केवल अंतरिक्ष यात्रियों तक सीमित नहीं रहता। अंतरिक्ष में हड्डियों और मांसपेशियों पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन पृथ्वी पर बुजुर्गों, लंबे समय तक बिस्तर पर रहने वाले मरीजों और विभिन्न शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे लोगों के उपचार में भी मदद कर सकता है। पहले भी अंतरिक्ष कार्यक्रमों से विकसित कई तकनीकें आम जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। संभव है कि डॉ. मेनन के शोध से प्राप्त निष्कर्ष चिकित्सा विज्ञान में नए आयाम स्थापित करें।

विज्ञान के इतिहास में कई महत्वपूर्ण खोजें मानव साहस और जिज्ञासा का परिणाम रही हैं। डॉ. अनिल मेनन का यह मिशन भी उसी परंपरा का विस्तार है। अगले 200 दिनों तक वे अपने शरीर को वैज्ञानिक अध्ययन का माध्यम बनाकर न केवल अंतरिक्ष विज्ञान, बल्कि मानव स्वास्थ्य की समझ को भी नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। उनकी यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि ज्ञान की खोज की कोई सीमा नहीं होती और मानवता की प्रगति के लिए कुछ लोग स्वयं को प्रयोग का हिस्सा बनाने का साहस रखते हैं।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)